THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) Yes, Sir. During his recent visit to India the President of Guyana, in his discussions, invited the Government and Indian businessmen to invest in Guyana and set up joint ventures.

(b) and (c) During the Indo-Guyanese Joint Commission meeting held in November, 1993 at Georgetown (Guyana) it was agreed in principle, to constitute a Joint Business Council for promoting regular inter-action between the private sectors of the two countries.

नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा श्रीलंका को लाल मिर्च का निर्यात

5304. **श्री वीरेन जे. शाह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों से श्रीलंका को लाल मिर्च का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान कितने-कितने मूल्य का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अवधि के दौरान फेडरेशन द्वारा घटिया किस्म की मिर्च का निर्यात किए जाने के कारण माल वापस आने की घटना भी हुई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान करके उन्हें निलम्बित कर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो उन कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(छ) क्या इन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध स्पष्ट आरोप लगा कर इन्हें अदालत द्वारा दण्डित कराने हेतु कोई कार्यवाही की गई है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस घटना के फलस्वरूप फेडरेशन को कितनी आर्थिक हानि होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ (नेफेड) द्वारा 1990-91 से किए और इस घटना के फलस्वरूप फेडरेशन को हैं :—

वर्ष	मात्रा मी० टन	मूल्य लाख रुपया
1990–1991	662	134.34
1991–1992	2888	985.15
1992–1993	शून्य	शून्य

स्रोत : नेफेड

(ग) जी, नहीं ।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान 137 एम टी (लगभग 44 लाख रुपए की) एक रूप बिना पोतलदान पूर्व निरीक्षण को भेज दी गयी थी । उसके लिए क्रेता ने 5% का (रुपया 2·2 लाख) गुणवत्ता दावा किया जिसे अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए स्वीकार कर लिया गया था ।

(ङ)से (ज) नेफेड के निम्नलिखित कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया गया :—

श्री एस. एस. मल्होत्रा, महाप्रबन्धक

श्री ए. सूर्यनारायण, महाप्रबंधक और

श्री वी. कृष्णा, प्रबन्धक

इन अधिकारियों को चार्जशीट दी गई और नेफेड ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है ।

नेफेड के अनुसार श्रीलंका को मिर्चों के निर्यात में कोई वित्तीय घाटा नहीं हुआ । वास्तव में इसने कुल निर्यात से वर्ष 1991-92 के दौरान लगभग 60 लाख रुपये का लाभ कमाया ।

Negative Subsidy in Agriculture

5305. SHRI SANJAY DALMIA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) what are the compulsions for Government to continue with negative subsidy in agriculture in the country;

(b) whether Government have made any study of its impact on GDP;

(c) if so, what are the details thereof;

(d) whether Government are aware that because of the existing negative agriculture subsidiy the Urban Sectors is reaping its benefits at the cost of rural poor; and

(e) if so, what steps/incentives Government are contemplating to counter-effect this imbalance to improve the lot of the rural poor particularly the weaker sections so that they become the real beneficiaries of their agricultural produce ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (e) The concept of the aggregate measurement of support (AMS) used in the Uruguay Round Agreement on Agriculture is a negotiated concept which is not designed to reflect the terms of trade of agriculture. The negative figure arises from the fact that in most agricultural commodities our support prices during the reference period, 1986-89 have been lower than the international prices. Government is allowing suitable increases in support prices for various agricultural commodities from year to year keeping in view increases in the cost of imports and need to provide a reasonable margin of profit to farmers.

Trade Policy Reforms

5306. DR. SHRIKANT RAMACHANDRA JICHKAR : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the New Trade Policy has been slow in implementation for want of clearance for such proposals on trade policy reforms; and

(b) by when these proposals are likely to be cleared ?